बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 173

अर्थव्यवस्था का प्रश्न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि वह निष्क्रिय है। उसके शुरुआती 100 दिन तो सक्रियता से भरे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक कदम उठाया गया, संसद के जरिये कई कानून पारित किए गए और स्वयं प्रधानमंत्री भूटान, जी-7, संयुक्त अरब अमीरात, रूस आदि की यात्रा पर गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद वह चीन जाएंगे। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि स्वर्गीय अरुण जेटली के बाद अमित शाह के सरकार में नंबर दो की हैसियत में आते ही सरकार के सुर और रुख में भी उल्लेखनीय बदलाव आया है।

इन सब के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रचार अभियान का एक नारा याद आना स्वाभाविक है। नारा था, 'इट्स दी इकॉनमी, स्टुपिड!' ऐसा नहीं है कि बीते 100 दिनों में अर्थव्यवस्था की अनदेखी की गई है। सरकारी बैंकों का विलय किया गया, बजट में तमाम बातें कही गईं, विदेशी निवेश के लिए माहौल और सहज बनाया गया। कुछ नए कानून अपनी प्रकृति में आर्थिक हैं: दो नए श्रम कानून, दिवालिया कानून में संशोधन। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दो बार दरों में कटौती की घोषणा की। इसके बावजूद वित्त मंत्री के अलावा सरकार में शामिल तमाम अन्य लोग वृहद आर्थिक नीति के मुद्दों से अलग-थलग नजर आ रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि कब अर्थव्यवस्था के समक्ष बढ़ती बेरोजगारी की चुनौती, कृषि संकट, विनिर्माण में ठहराव और निर्यात में गिरावट की समस्या आती है।

बिल क्लिंटन के पुराने नारे ने हकीकत बयानी के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन वर्तमान की तरह कई बार सच को कहे जाने की जरूरत होती है। खासतौर पर जब मोदी की पिछली आर्थिक पहलों की तरह उनकी नई आर्थिक पहल में भी सरकारी धन को खर्च करने संबंधी कदम शामिल हैं। वह किसानों को धनराशि देने और सरकारी फंड की मदद से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जैसे कदम उठा चुके हैं। अर्थव्यवस्था में धीमापन आने के साथ-साथ लगातार दूसरी बार कर राजस्व के अनुमान से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। इन तथा अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सरकार के पास नहीं है।

आर्थिक मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन से कई बड़ी जटिलताएं जुड़ी हुई हैं। बदलती विश्व व्यवस्था में जहां राष्ट्र-राज्य खुली छूट चाहते हैं, वैसे में देश का अधिकांश बाहरी प्रवाह प्रत्यक्ष तौर पर उसकी सामरिक स्थिति और इसके बाजारों के भविष्य पर निर्भर करता है। अगर वृद्धि रुक जाती है, तो देश को चीन के स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखे जाने की संभावना कम हो जाती है। आर्थिक शब्दावली में इसे अगला चीन नहीं माना जाता। यह बात ध्यान रहे कि ये अवधारणाएं ही अमेरिका के भारत के साथ दोबारा रिश्तों को कायम करने के लिए जिम्मेदार रहीं। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति बुश के दूसरे कार्यकाल में नाभिकीय पहल के आरंभ के साथ हुई थी।

अगर अमेरिका अब यह तय कर लेता है कि भारत का भरपूर इस्तेमाल हो चुका है (अमेरिका में कई पर्यवेक्षक ऐसा कहने भी लगे हैं) तो इसकी एक कूटनयिक कीमत चुकानी होगी। संभव है कि कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के विरोध के चलते अन्य देश भारत की बातों पर एकबारगी यकीन नहीं करेंगे। रक्षा बलों को भी कुछ कीमत चुकानी होगी क्योंकि नई पनडुब्बियों और विध्वंसक पोतों के लिए धन नहीं है जबकि चीन की नौसेना हिंद महासागर में बहुत तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रही है। ऐसे में सामरिक साझेदार की भारत की उपयोगिता सीमित हो रही है।

अगर हमारे कारोबारी संरक्षणवादी दरों की तलाश में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी सरकार पर एक बड़े कारोबारी समझौते, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने का दबाव बनाते हैं तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत हिस्से की ओर अपनी पीठ मोड़ लेगा। सरकार की बात करें तो ऐसा लगता है कि उसने यह तय कर लिया है कि मेक इन इंडिया केवल आयात प्रतिस्थापन से ही सफल होगा। यह कदम उच्च शुल्क दर की वजह बनता है। अगर विश्व व्यापार और आर्थिक प्रदर्शन का इतिहास देखा जाए तो यह नीति लंबी अवधि में कारगर नहीं साबित होती।

प्रधानमंत्री समेत सरकार के तमाम प्रमुख लोगों को प्रत्यक्ष सक्रियता दिखाते हुए मौजूदा मंदी को रोकने का प्रयास करना होगा। मोदी को वृहद आर्थिक नीतियों से अपनी दूरी कम कर सुधार की नीति के विभिन्न तत्त्वों की सही समझ विकसित करनी होगी। सरकार को यह देखना होगा कि क्या किया जाना है क्योंकि ढांचागत मुद्दे मौसम के साथ नहीं बदलते।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

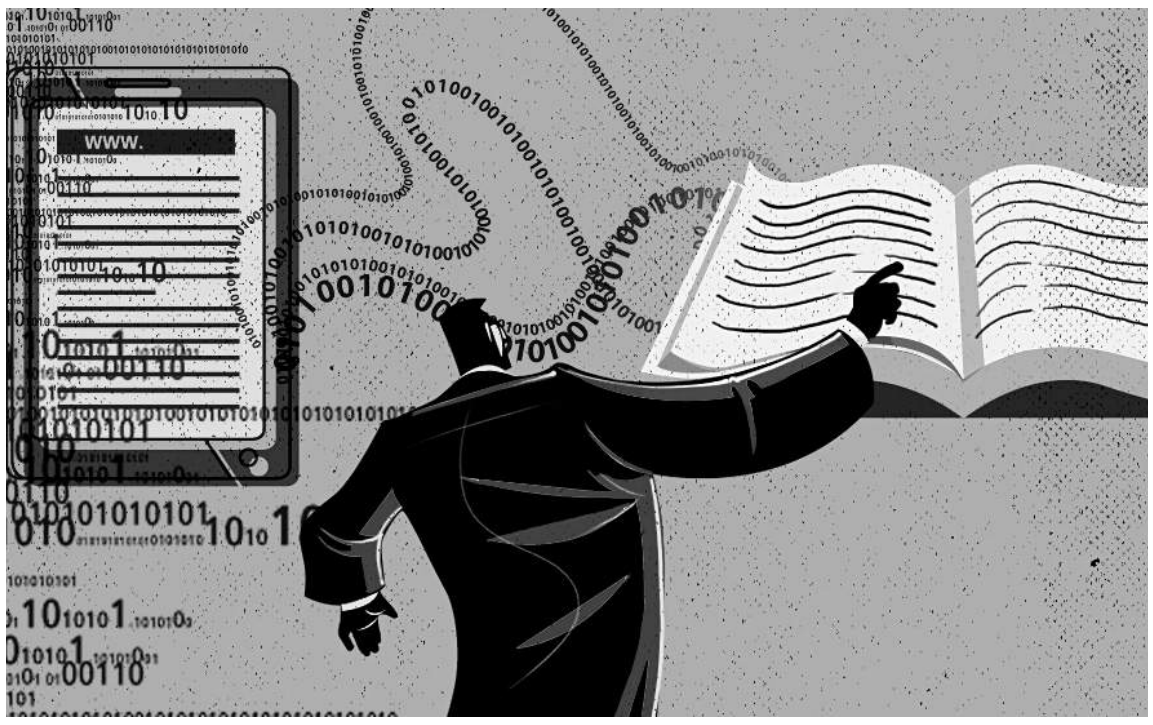

अजय मोहंती

वेब के प्रतिगामी दौर में किताब की वापसी

वर्ल्ड वाइड वेब के प्रसार ने कभी ई-बुक को रफ्तार दी थी लेकिन इसकी जटिलताओं ने अब उलटी चाल चलने को मजबूर कर दिया है। इस नए रुझान पर रोशनी डाल रहे हैं अजित बालकृष्णन

जब मुझे यह अहसास हुआ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक किताबों की तुलना में हाल-फिलहाल छपी हुई किताबें पढ़ना काफी पसंद करने लगा हूं तो मैं आदत में आए इस बदलाव पर गौर करने से खुद को नहीं रोक पाया। पिछले दो दशकों से किंडल जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध किताबें ही खरीदकर पढ़ता आया था। एक और अहम बात यह है कि हाल में खरीदी गई किताबों में 'डूइंग डेटा साइंस' और 'न्यूरल नेटवर्क्स विद आर' जैसी तकनीकी विषयों वाली किताबें शामिल हैं।

पहले तो मैंने इस बदलाव को यह कहते हुए सही साबित करने की कोशिश की कि मैं तो बस व्यावहारिक होने की कोशिश कर रहा था। कंप्यूटर कोड इतने सघन होते हैं कि किंडल पर उन्हें पढ़ पाना आसान नहीं होता है। आखिरकार, अगर कोई एक कारोबार इंटरनेट के प्रसार को दर्शाता है तो वह जेफ बेजोस का एमेजॉन है जो वर्ष 1995 में इंटरनेट पर किताबें बेचने वाले स्टोर के तौर पर ही शुरू हुआ था।

दुनिया का पहला ऑनलाइन स्टोर किताबों की बिक्री के साथ क्यों शुरू हुआ था? एमेजॉन के बारे में विकीपीडिया का पेज इस बात को नहीं बताता है लेकिन उस दौर में मौजूद रहने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों अमेरिका में किताब उद्योग को बुकस्टोर में 40 फीसदी से भी अधिक मार्जिन मिलता था। इस वजह से एमेजॉन के लिए संभावित खरीदारों को बड़ी छूट की पेशकश कर ऑनलाइन किताबें खरीदने के लिए लुभा पाना आसान लगा। हमें वर्ष 2004 में वायर्ड के संपादक क्रिस एंडरसन की किताब 'द लॉन्ग टेल: व्हाई द फ्यूचर ऑफ बिज़नेस इज सेलिंग लेस ऑफ मोर' आने पर ही इसके पीछे की एक और वजह पता चल पाई। एंडरसन ने हमें बताया था कि किताब उद्योग जैसे उद्योगों में किताबों की बड़ी संख्या को पढ़ने वाले कम लोग ही होते हैं। ये समर्पित पाठक एक 'लॉन्ग टेल' बनाते हैं और वे बेस्ट सेलर किताबें पढ़ने में रुचि रखने वाले पाठकों की तुलना में किसी किताब की बढ़िया कीमत भी चुकाने को तैयार होते हैं। वहीं बेस्ट सेलर किताबों के शौकीनों को आकर्षित करने के लिए उन्हें भारी छूट की पेशकश करनी पड़ती है। इस 'लॉन्ग टेल' मॉडल को उसके बाद कई दूसरे उद्योगों ने भी अपनाया है और इस बात को कहा जा सकता है कि ऑनलाइन खरीदारी में इस मॉडल की केंद्रीय भूमिका होती है। इसकी शुरुआत छपी हुई किताबों के उद्योग से ही हुई थी।

वर्ष 1989 में इंटरनेट के आधार वर्ल्ड वाइड वेब की सोच लेकर आने वाले टिम बर्न्स-ली चाहते थे कि ज्ञान का आदान-प्रदान सरल हो जाए। और उनकी संकल्पना शुरुआती 15 वर्षों तक इस लक्ष्य पर खरा उतरने में सफल रही। हम सभी वेब पर मौजूद बेशुमार जानकारियों को मुफ्त में पढ़कर खुश होते रहे। इसके अलावा मुफ्त में संगीत सुनने और वीडियो एवं फिल्में भी देखने की सुविधा थी।

सवाल उठता है कि इतना सब होते हुए भी आखिर किस वजह से मैं दोबारा छपी हुई तकनीकी किताबें पढ़ने लगा? इसकी पहली वजह यह है कि वेब पर किसी मुद्दे पर जानकारी के लिए सर्च करने के बाद जब मैं किसी वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री पढ़ना शुरू करता था तो कुछ पंक्तियों के बाद ही 'अधिक जानकारी के लिए ग्राहक बनें' वाला बैनर नजर आने लगता था।

मैं ग्राहकी लेने में हिचकता था क्योंकि कई बार भुगतान करने के बाद जब मैं उस पेज को विस्तार से पढ़ना शुरू करता था तो कुछ समय बाद 'हमारी ई-बुक डाउनलोड करें' वाला एक और बैनर नमूंदार हो जाता था। यहां पर मैं फिर से हिचकता था क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ था कि डाउनलोड किए गए संस्करण में भी वे सारी जानकारियां नहीं होती थीं जो मुझे उस किताब के प्रकाशित संस्करण में मिलती थीं।

मेरे दिमाग में यही सवाल उपजता था कि क्या पिछले दो दशकों में वर्ल्ड वाइड वेब महज प्रचार का जरिया बनकर रह गया है? यह एक ऐसा उपकरण हो गया है जिसका इस्तेमाल आपको लुभाने और एक छपी पुस्तक खरीदने के लिए प्रेरित करने में होता है।

विद्वान एवं प्रबंधन सिद्धांतकार कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ने तीन बुनियादी तरीके से हमारी जिंदगियों पर असर डाला है। पहला तरीका, यह मध्यवर्तियों की भूमिका खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि चीन के शेन्जेन में स्थित एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वेब के जरिये मुंबई में स्थित मेरे जैसे उपभोक्ता तक सीधे अपना उत्पाद बेच सकती है जिससे वह वितरकों को कमीशन देने से बच जाती है। इस तरह यह संकल्पना रखी गई कि वेब के आगमन ने 'मध्यवर्ती-उन्मूलन' कर अर्थव्यवस्था को उसी तरह कारगर बनाया है जिस तरह औद्योगिक क्रांति के समय व्यापक उत्पादन ने किया था। दूसरा तरीका है 'अभौतिकीकरण' जिसका सबसे अच्छा उदाहरण उस तरह का संगीत है जो अब भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रह गया है, मसलन ग्रामोफोन रिकॉर्ड और कैसेट टेप। लेकिन अभौतिक रूप में स्ट्रीमिंग के तौर पर ऐसे संगीत अब भी मौजूद हैं।

हमारी जिंदगी पर असर डालने का तीसरा तरीका 'विसमूहन' का है। मसलन, हम जिसे बैंक के रूप में जानते रहे हैं अब वह वेब प्रसार के दौर में भुगतान कंपनी और कर्जदाता कंपनी के रूप में विखंडित हो चुका है।

वेब के काम करने के इन तरीकों का इस्तेमाल कर लाभ कमाने के लिए बड़ी मात्रा में निजी निवेश एवं वेंचर गतिविधियां संचालित हो रही हैं। समकालीन दौर में उद्यमशीलता का आशय ऐसा कारोबार शुरू करने से रह गया है जो इन तीनों में से किसी एक तरीके पर निर्भर हो।

इस परिदृश्य में मुझे ई-बुक के बजाय छपी किताबों की तरफ लौटने की घटना को किस तरह लेना चाहिए? क्या ऐसा कोई भी मामला सामने आया है कि औद्योगिक क्रांति के पलटने की स्थिति पैदा हो रही हो? मेरे दिमाग में तात्कालिक तौर पर यही बात आती है कि रासायनिक औद्योगिक क्रांति के उप-उत्पादों के बारे में विश्वव्यापी धारणा अब पलटने लगी है। नील के संश्लेषण से रासायनिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और किफायती सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक कपड़ों एवं पेट्रोरसायन जैसे उत्पादों के बल पर यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। लेकिन आज के दौर में प्लास्टिक, पेट्रोल एवं सिंथेटिक रसायनों के खिलाफ आवाज बुलंद होने के साथ ही यह क्रांति भी अब प्रतिगामी हो चली है। क्या छपी हुई किताबों के प्रति भी इसी तरह का रुझान दस्तक दे रहा है?

शिवकुमार की बहुमुखी प्रतिभा सबके लिए फायदे का सौदा

कांग्रेस नेता डोड्डलहल्ली केंपेगौड़ा (डीके) शिवकुमार को इस सप्ताह के आरंभ में कथित धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य होने के बावजूद शिवकुमार प्रांत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करवाने में कामयाब रहे।

रामनगर, चेन्नपट्टना और उसके आसपास के इलाके शिवकुमार के विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा में आते हैं। इन इलाकों में बंद का आह्वान किया गया और तमाम स्कूल बंद हो गए। सरकारी बसों पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थर फेंके गए। जाहिर सी बात है शिवकुमार न केवल बहुत लोकप्रिय हैं, बल्कि वह इतने संसाधन संपन्न भी हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों से ऐसा विरोध प्रदर्शन करा सकते हैं। कांग्रेस के इस रणनीतिकार में कई और गुण हैं। यहां तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा तक ने उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस जाहिर किया।

आखिर कौन हैं डी के शिवकुमार?

वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए दिए शपथपत्र में उन्होंने और उनकी पत्नी ने 730 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया। वह कुछ भी लिख सकते थे लेकिन दक्षिण कर्नाटक में सत्ता की चाबी जमीन और जाति ही है। शिवकुमार वोक्कालिंगा समुदाय के हैं। वह उसी इलाके के एक कृषक परिवार में पैदा हुए है जहां एचडी देवेगौड़ा पैदा हुए। देवेगौड़ा को कर्नाटक में वोक्कालिंगा समुदाय का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। स्वाभाविक था कि देवेगौड़ा उन्हें लंबे समय तक नौसिखुआ के तौर पर देखते रहे।

शिवकुमार कॉलेज के दिनों से ही कांग्रेस में हैं। सबसे पहले उन्होंने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली। सन 1983 से 1985 तक वह प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। उनकी पहली चुनावी जीत सन 1987 में हुई जब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। सन 1985 में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा के खिलाफ साथनूर से चुनाव लड़ा। वह मामूली अंतर से चुनाव हार गए। यह भी उनके लिए एक उपलब्धि की तरह थी क्योंकि

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

शिवकुमार कॉलेज के दिनों से ही कांग्रेस में हैं। सबसे पहले उन्होंने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली। सन 1983 से 1985 तक वह प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। उनकी पहली चुनावी जीत सन 1987 में हुई जब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता।

देवेगौड़ा तत्कालीन रामकृष्ण हेगड़े सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे। देवेगौड़ा ने दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने साथनूर सीट छोड़ दी। शिवकुमार वहां से दोबारा लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद देवेगौड़ा परिवार के साथ उनका विवाद आरंभ हुआ जो अपना रूप बदलता रहता है लेकिन अब तक बरकरार है।

शिवकुमार ने सन 1989 में कनकपुरा लोकसभा क्षेत्र से देवेगौड़ा के खिलाफ चुना लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय देवेगौड़ा शिखर पर थे। परंतु इस हार के बावजूद शिवकुमार ने बेंगलूरु के आसपास के ग्रामीण इलाकों में पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। यही वह दौर था जब जमीन की कीमतें बढ़ रही थीं। शिवकुमार ने भी खनन और उससे जुड़े कारोबार में निवेश किया। उन्होंने सन 1989 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीत गए। दो वर्ष बाद 30 की उम्र में वह प्रदेश के सबसे युवा मंत्री बन गए। सन 1991 से 1992 तक वह एस बंगारप्पा की सरकार में राज्य मंत्री रहे। इसके बाद एसएम कृष्णा की सरकार आई। शिवकुमार ने कृष्णा के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए। कहा जाता है कि कृष्णा के दामाद स्वर्गीय वीजी सिद्धार्थ के कैफे कॉफी डे के कारोबार में भी उनका पैसा लगा हुआ है। वह अब तक सात बार विधायक रह चुके हैं। उनकी कारोबारी गतिविधियां और उनकी राजनीतिक मेहनत ने भी उनका खूब साथ दिया है।

शिवकुमार ने व्यक्तिगत संपदा के बल पर राजनीतिक पूंजी तैयार की। ये किस्से सभी जानते हैं। सन 2002 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय विलासराव देशमुख की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण लगभग गिरने को थी, तब कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री डी के शिवकुमार ने विधायकों को ईगलटन रिजॉर्ट में एकत्रित किया और मतदान के दिन उन्हें मुंबई ले गए। अगर वहां की दीवारें बोल सकतीं तो जाने कितने रहस्य सामने आते। अहमद पटेल गुजरात में राज्यसभा सीट इसलिए जीत सके क्योंकि शिवकुमार ने 44 विधायकों को सुरक्षित रखा। बाद में उन्होंने हैदराबाद में अपने कारोबारी रिश्तों का इस्तेमाल किया और वह विधायकों को बेंगलूरु से हैदराबाद स्थित एक रिजॉर्ट में ले गए। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से केवल इतनी गुजारिश की कि वह विधायकों को सुरक्षित रखें। यही वजह थी कि 224 में से 104 विधायक होने के बावजूद येदियुरप्पा मुंह ताकते रह गए और राज्य में एच डी कुमारस्वामी व कांग्रेस की सरकार बनी। इस अभियान में शिवकुमार ने अमित शाह तक को पछाड़ दिया था।

देवेगौड़ा का परिवार और शिवकुमार कभी मित्र नहीं रहे। वे केवल रणनीतिक सहयोगी हैं। कांग्रेस में तमाम अन्य नेताओं की तरह शिवकुमार के बारे में भी कुमारस्वामी ने यही सोचा कि वह उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। यही कारण है कि जनता दल सेक्युलर ने भी उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर खूब शोर मचाया।

सवाल यह है कि अब क्या होगा? लोग कह सकते हैं कि शिवकुमार का राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। परंतु वह कई लोगों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। वही उनकी मूल प्रतिभा है।

कानाफूसी

गठबंधन पर अटकल

बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी एक वर्ष की देरी है। पटना और दिल्ली में अटकलें हैं कि पता नहीं जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन चुनावों तक बरकरार रहेगा भी या नहीं। जदयू के उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, उनसे माहौल एक बार फिर गर्म है। भाजपा नेता नित्यानंद राय फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और अगर गठबंधन टूटता है तो भाजपा उन्हें अपना चेहरा बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक हालांकि कुमार के गठबंधन तोड़ने की संभावना नहीं है। वहीं विपक्षी दलों में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार चेहरों की कमी नहीं है। तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी जैसे कई नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। फिलहाल कांग्रेस देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रही है।

पर्यावरण के अनुकूल अभियान

हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आगामी 8 सितंबर को रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ शुरू हो रहा है। इस रैली को पर्यावरण के अनुकूल रैली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इस रैली में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का प्रयोग न्यूनतम रखने की कोशिश की जाएगी। रैली में भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी कपड़े से बनाया जाएगा। इस दौरान पानी के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस काम के लिए 10,000 मटकों का प्रयोग किया गया है। मंच तैयार करने में भी न्यूनतम प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा। गत लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पार्टी विधानसभा चुनाव में भी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। गौरतलब है कि रोहतक कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है।

आपका पक्ष

ट्रैफिक चालान और लोगों की मानसिकता

यातायात नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों के बीच कई धारणाएं सामने आ रही हैं। एक ओर जुर्माने में बढ़ोतरी का कारण यातायात नियमों का उल्लंघन रोकना है तो दूसरी ओर लोग भारी जुर्माना लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो देश में यातायात नियमों का उल्लंघन इतना होता है जितना शायद ही किसी अन्य कानून का होता हो। कुछ लोग अपना रौब दिखाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कुछ लोग जानकारी के अभाव में नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। अगर देश में दुर्घटनाओं से मरने वालों की संख्या देखी जाए तो यह बीमारी से मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। हमें यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए क्योंकि किसी दुर्घटना में उस व्यक्ति की मौत होती है जिसे कोई वाहन टक्कर मारता है। दुर्घटना में बेकसूर लोग दूसरे की लापरवाही के कारण मारे जाते हैं। अत: यातायात नियमों को तोड़ने वाली मानसिकता बदलनी होगी और इसका कड़ाई से पालन करना होगा। इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा यातायात पुलिस को भी अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि यातायात पुलिस ट्रैफिक लाइट के पास खड़े होने के बदले किसी कोने में छुपे रहते हैं तथा जब कोई सिग्नल तोड़ता है तो लपक कर उसे पकड़ते हैं और चालान काटते हैं। यातायात पुलिस को ऐसी मानसिकता भी बदलनी होगी तथा उन्हें पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

अनुष्का कुमारी, नोएडा

झारखंड की राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक के पास जांच करती ट्रैफिक पुलिस -पीटीआई

विदेशों के बजाय देश में पर्यटन को बढ़ावा

अर्थव्यवस्था में जारी मंदी के दौर से बाहर आने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उद्योगों को दी गई राहत कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य अवश्य करेगी। इस विषय में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण केंद्र सरकार द्वारा देश के बाहर से आ रहे उत्पाद व देश में बन रहे उत्पाद की लागत की तुलना किया जाना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि देश को उद्योगों की दशा व दिशा सुधारने के लिए वह उनका संरक्षण अवश्य करे और बाहर से आ रहे उत्पाद की तुलना में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर तकनीक व कम कर की व्यवस्था बना कर रखे। इससे बाहर से आ रहे उत्पाद यहां के उत्पाद के मुकाबले में कमजोर नहीं पड़े। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील कि दो वर्ष में परिवार के साथ कम से कम पांच स्थान देश में भ्रमण करें जिससे खर्च का पूरा लाभ देश को ही मिल सकेगा तथा पर्यटन उद्योग को संबल मिल सके।

कपिल करवा माहेश्वरी, हनुमानगढ़

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।